



पंचदश

बिहार विधान-सभा

षष्ठम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

बर्ग-5

12 द्वावण, 1934 (श०)

शुक्रवार, तिथि

03 द्वावण, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—05

(1) स्वास्थ्य विभाग	03
(2) कर्मों विभाग	02
		कुल योग	05

सीट बढ़ाना

1. श्री गिरिधारी यादव—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्र 2012 के लिये राज्य में 11 मेडिकल कॉलेजों के लिये 900 सीटों की संख्या निर्धारित की गयी है, जबकि 2011 में 10 मेडिकल कॉलेजों के लिये 1020 की संख्या निर्धारित की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में 2395 सीटों की बढ़ोतरी मेडिकल कॉलेजों में की गयी है परन्तु बिहार में सीटें घटा दी गयी हैं जिससे यहां के गरीब और मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रण्यहित में मेडिकल कॉलेज के सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के लिये कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

2. श्री संजय सिंह टाडगर—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को तीस शय्या वाले अस्पतालों में विस्तार हेतु वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में 6 अरब रुपये आवंटित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि राशि की उपलब्धता के बावजूद अबतक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार कराने तथा किलम्व के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों पर कार्रवाई का विचार रखती है ?

उच्चस्तरीय जांच करना

3. श्री मंजीत कुमार सिंह—दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 1 जुलाई, 2012 में प्रकाशित "16 (सोलह) हजार महिलाएं के निकाल दिये गये गर्भारण" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 20 वर्ष से 30 वर्ष के आयु वाले सोलह हजार से ऊपर महिलाओं को गर्भारण वर्ष 2010 से जून, 2012 तक ग्यारह जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि हड़पने के लिए निकाल दिये गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार से सूचीबद्ध 829 निजीअस्पताल, गरीब परिवारों को बीमा करने एवं उन्हें स्मार्ट कार्ड देने के लिए चार-पांच कम्पनियों से समझौता किया है जिसके एवज में राज्य एवं केंद्र सरकार से प्रीमियम प्राप्त होता है;

(3) क्या यह बात सही है कि बीमा कम्पनियों राज्य के अस्पताल के डाक्टर तथा सूचीबद्ध निजी अस्पताल के मेल-जोल से ग्यारह जिलों में सी करोड़ से ऊपर की राशि का बारा-न्यारा कर मामूम महिलाओं को संतान उत्पत्ति से बंचित कर दिया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्यारह जिलों में हुई अमानवीय घटनाओं तथा राशि की बंदरबांट की उच्चस्तरीय जांच करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वयन करना

4. श्री विनोद नारायण झा—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने बरीली थर्मल पावर को 3666 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 250-250 मेगावाट की दो बिजली इकाइयों के लिए कोल लिसेज देने से इनकार कर दिया है, यदि हां, तो इन दोनों इकाइयों के कार्यान्वयन हेतु अब सरकार की क्या कार्य योजना है ?

विद्युत मीटर लगाना

5. श्री जितेन्द्र कुमार राय—दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 17 मई, 2012 के अंक में छपी खबर “हर तीसरा बिजली उपभोक्ता बगैर मीटर के” शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह कतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 33 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 11 लाख से अधिक उपभोक्ता बिना मीटर के बिजली का उपयोग कर रहे हैं और 1 लाख से ऊपर उपभोक्ताओं के मीटर 2 वर्षों से ऊपर से खरब है;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 12 लाख उपभोक्ताओं द्वारा बिना मीटर के बिजली का उपयोग करने के कारण बिजली विभाग को हर वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्युत मीटर लगवाकर सरकारी राजस्व की क्षति को रोकने एवं इसके लिए दीर्घियां पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 03 अगस्त, 2012 (ई०) ।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।